जब तक कांच है तबतक
चुभेंगे जिस दिन
आईना बन गए दुनिया
देखेगी।
– अज्ञात

परिजनों को मुआवजा देने का सवाल

सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि देश में उत्पन्न हुई उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए बिना किसी तैयारी और पूर्वसूचना के अचानक देश भर में पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का उसका फैसला जिम्मेदार था। लॉकडाउन से सारे काम धंधे बंद हो गए।

नवीन वर्मा।।

लॉकडाउन के दौरान अमानवीय परिस्थितियों में भीषण तकलीफें झेलते हुए अपने–अपने गांवों की ओर सफर करने के क्रम में जान गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के प्रति केंद्र सरकार का जो रुख सामने आया है वह न केवल गैरजिम्मेदार और संवेदनहीन है बल्कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए शर्मनाक भी है। लॉकडाउन के बहुचर्चित फैसले के बाद आयोजित संसद के इस पहले सत्र में प्रवासी मजदूरों का यह मसला स्वाभाविक रूप से उठा। एक सांसद के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने माना कि उस दौरान एक करोड़ से ज्यादा मजदूर देश के अलग–अलग हिस्सों से बदहवासी के आलम में अपने अपने गांवों की ओर चल पड़े थे। मगर इसके साथ ही उसका कहना है कि इस यात्रा में जान गंवाने वाले मजदूरों का कोई आंकड़ा उसके पास नहीं है, इसलिए उन मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। यह भी गौर करने की बात है कि सरकार ने अचानक शुरू हुए उस पलायन के लिए फेक न्यूज को जिम्मेदार ठहराया है।

सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि देश में उत्पन्न हुई उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए बिना किसी तैयारी और पूर्वसूचना के अचानक देश भर में पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का उसका फैसला जिम्मेदार था। लॉकडाउन से सारे काम धंधे बंद हो गए। बड़े शहरों में रोज मेहनत करके परिवार पाल रहे लोगों की आमदनी का जरिया समाप्त हो गया। कई मकान मालिकों ने किराया न मिलने की आशंका में उन्हें बाहर निकालकर कमरे पर ताला मार दिया। परिवार सहित बेघर रहने और भूखों मरने की स्थिति से बचने का मजदूरों को एक ही उपाय नजर आया कि किसी तरह अपने गांव पहुंच जाएं। लॉकडाउन के चलते बस–ट्रेन सब बंद थीं।

मजबूरन सैकड़ों मील लंबी दूरियां उन लोगों ने पैदल ही नापने का फैसला किया। बाद में नैतिक दबाव की स्थिति में जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें सरकार ने चलवाईं वे भी तमाम अव्यवस्थाओं की शिकार रहीं। बहुत सी मौतें ट्रेन में भूख–प्यास और असह्य गर्मी के चलते हुईं जबकि कई मौतें सड़क और ट्रेन दुर्घटनाओं में हुईं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने इन मौतों से जुड़ी सूचनाएं जुटाने की जहमत नहीं उठाई। फिर भी इसे बहाना बनाकर मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की अपनी जिम्मेदारी से सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती। सूचनाएं अब भी जुटाई जा सकती हैं।

अखबारों में ब्यौरेवार खबरें मौजूद हैं। रेलवे के पास उसके रेकॉर्ड होंगे। अस्पताल, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के पास जानकारी होगी। कुछ मौतें ऐसी हो सकती हैं जिनकी रिपोर्ट न आ पाई हो। उनके बारे में सूचनाएं अखबारों में नोटिस देकर मंगवाई जा सकती हैं और मुआवजे के दावों की सचाई कई तरीकों से जांची जा सकती है। लेकिन जिन गरीब परिवारों के कमाने वाले सदस्य मारे गए हैं वे आज भी बहुत बुरी दशा में हैं। इस राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय आपदा के समय अपने देश की सरकार से सहानुभूति और सहायता प्राप्त करना उनका अधिकार है।

ध्यान भंग

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

कहते हैं कि उन्होंने अप्सराओं के बहकावे में आकर शिवजी का ध्यान भंग करने का यत्न किया था। इस अपराध के कारण शिवजी ने शाप देकर उन्हें कबूतर बना दिया, तभी से वे गुफा के चक्कर काटते दिखाई देते हैं। श्रीअमरनाथ मंदिर के दर्शन करके लौटते समय यात्रियों को सच्ची शांति का अनुभव होता है। सामान्य जीवन जीने के लिए तथा जीवन में स्वाभाविक गति से प्रगति एवं विकास करने के लिए शान्ति का बना रहना अत्यन्त आवश्यक होता है। देश में व्यापार की उन्नति व आर्थिक विकास भी शान्त वातावरण में ही संभव हो पाता है। सहस्त्र वर्षों के अथक प्रयत्न व साधन से ज्ञान–विज्ञान, साहित्य–कला आदि का किया गया विकास युद्ध के एक ही झटके से मटिया–मेट हो जाता है।

संपादकीय

भविष्य दांव पर

प्रधानमंत्री के जन्मदिन (17 सितंबर) को लोगों ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से इसे जोड़ने की अपील भी हो रही है। संभव है, इसी स्वतःस्फूर्तता के बीच से आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित एकताबद्ध छात्र–युवा आंदोलन की शक्ल उभरे। हाल ही में ठीक उस समय जब लगभग 2 करोड़ वेतनभोगी नौकरियों के जाने की बात आम बहस में आई, सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती प्राधिकरण (एनआरए) की घोषणा कर दी। मीडिया में ऐसे प्रचारित किया गया जैसे नौकरियां जाने की समस्या का हल मिल गया, जबकि मामला महज इतना था कि अब सभी विभागों की बहुस्तरीय परीक्षाओं के लिए एक संयुक्त स्क्रीनिंग टेस्ट एनआरए के माध्यम से करवाया जाएगा। इन सबके साथ एक और खतरनाक खेल खेला जा रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि रोजगार का प्रश्न सर्वोच्च प्राथमिकता का राष्ट्रीय मुद्दा बने। केंद्र और राज्यों के सभी खाली पदों के लिए परीक्षाएं समयबद्ध कार्यक्रम के तहत 6 महीने में पूरी करवाकर नौजवानों को नियुक्ति दी जाए। सबके लिए रोजगार सृजन की अर्थनीति लाई जाए। रोजगार को संविधान का मौलिक अधिकार बनाया जाए और रोजगार मिलने तक बेरोजगारों को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाए। गांधी जी के विशेष आग्रह पर संविधान में रोजगार का अधिकार शामिल जरूर किया गया पर उसे मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया गया। समय आ गया है कि रोजगार के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए जाएं।

वैसे तो इस आंदोलन की गूंज काफी बड़े क्षेत्र में थी लेकिन इलाहाबाद जैसे प्रतियोगी छात्रों के गढ़ इसका केंद्र बने। रोजगार के प्रश्न पर युवाओं के सड़क पर उतरने की संभावना को लेकर सरकार कितनी चौकस है।

नहीं मिला रोजगार

लाल बहादुर सिंह।।

नौ सितंबर को रात 9 बजे देश भर में लाइट बुझाकर, मोबाइल, टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन जलाकर युवाओं ने अपने गुस्से का इजहार किया। इसके पहले 5 सितंबर को बहुत बड़ी तादाद में नौजवान स्वतःस्फूर्त ढंग से ताली–थाली बजाते हुए सड़कों पर उतरे। वैसे तो इस आंदोलन की गूंज काफी बड़े क्षेत्र में थी लेकिन इलाहाबाद जैसे प्रतियोगी छात्रों के गढ़ इसका केंद्र बने। रोजगार के प्रश्न पर युवाओं के सड़क पर उतरने की संभावना को लेकर सरकार कितनी चौकस है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ताली–थाली आंदोलन के एक घंटे के अंदर सरकार ने रेलवे की लगभग डेढ़ साल से लटकी परीक्षाओं को 15 दिसंबर से आयोजित करने का ऐलान कर दिया।

मोदी जी ने 2014 के चुनाव अभियान में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को जॉबलेस ग्रोथ के लिए कठघरे में खड़ा करते हुए रोजगार के प्रश्न को बड़ा मुद्दा बनाया था। उन्होंने भारत को चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना दिखाया था और हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। उनके सत्ता में आने के बाद रोजगार सृजन की दिशा में तो कुछ हुआ नहीं, उलटे उनकी नीतियों, विशेषकर नोटबंदी, जीएसटी

आदि के फलस्वरूप हालात बद से बदतर होते गए। जब यह राजनीतिक मुद्दा बनने लगा और युवाओं में नाराजगी बढ़ने लगी तो 2019 के चुनावों के पहले केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों के लिए विज्ञापन निकाले गए।

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 23 फरवरी 2019 को ग्रुप डी के 1,03,769 पदों के लिए अधिसूचना जारी की। 1.16 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, जिनसे रु 500– प्रति फॉर्म (एससीएसटीओमहिला से रु 250– प्रति फॉर्म) लिया गया जो अनुमानतः कुल 1025 करोड़ रुपये हुआ। डेढ़ साल से अधिक बीत जाने के बाद भी अब तक उसकी परीक्षा नहीं हुई। 28 फरवरी, 2019 को रेलवे की ही नॉन–टेक्निकल पॉप्युलर कैटेगरी (जिसमें गार्ड, टीटीई वगैरह आते हैं) के 36,277 पद विज्ञापित हुए जिसके लिए 1.26 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन 18 महीने बीत जाने के बावजूद उसकी भी परीक्षा अब तक नहीं हुई। 3 फरवरी, 2018 को विज्ञापित 64,371 असिस्टेंट लोको पायलट तथा टेक्नीशन के पदों के लिए हुई परीक्षा का परिणाम दिसंबर 2019 में आ गया लेकिन नियुक्तियां 2 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हुईं। इसी तरह स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (एसएससी) ने 5 मई, 2018 को कंबाइंड ग्रैजुएट लेवल (ब्ळस्) के 11271 पद विज्ञापित किए। 25 लाख प्रतियोगी छात्रों ने फॉर्म भरा, 3–स्तर की परीक्षाएं हो गईं लेकिन ढाई साल होने को आए, रिजल्ट का कहीं पता नहीं।

इस दौरान मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार के तमाम विभागों में लगभग 7 लाख पद खाली हैं जिनमें से 408591 पदों के लिए एसएससी, रेलवे बोर्ड आदि के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है लेकिन उनके बयान के एक साल बाद भी वे भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं। इन सबसे युवाओं के मन में जमा हो रहे आक्रोश की झांकी 5 सितंबर के ताली–थाली कार्यक्रम और 9 सितंबर के टॉर्च–लाइट कार्यक्रम में दिखी। माना जा रहा है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री के तमाम विडियो पर डिस्लाइक्स की जो बाढ़ आई है, उसके पीछे भी इन्हीं युवाओं का गुस्सा है।

सूडोकु नवताल-5478

सरल

6					7			
		8	2				7	5
	4			3				6
	7	1			2		5	
8				4				3
	2		8			9	6	
2				8			3	
4	3				9	8		
			3					9

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5477 का हल

7	4	6	9	1	5	8	3	2
1	5	2	8	3	7	4	6	9
9	3	8	2	6	4	7	1	5
8	6	4	7	9	1	5	2	3
5	2	7	3	4	6	9	8	1
3	9	1	5	8	2	6	7	4
2	7	9	1	5	8	3	4	6
6	1	5	4	7	3	2	9	8
4	8	3	6	2	9	1	5	7

अपना ब्लॉग

इस चुनौती से कैसे निपटती है सरकार

मोहन। अब सरकार पर है कि वह इस चुनौती से कैसे निपटती है। एक रास्ता दमन का है। 5 सितंबर के आंदोलन को लेकर इलाहाबाद में युवा मंच के 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 4 सितंबर को भोपाल में लाठीचार्ज और गिरफ्तारी हुई। लेकिन दमन का रास्ता आत्मघाती साबित होगा और आग में घी डालने का काम करेगा। ध्यान भटकाने की कोशिशें भी जारी हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एलान किया कि अब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां केवल मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिलेंगी। देश के एक प्रमुख राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि देश के ही दूसरे राज्यों के लोग वहां सरकारी नौकरी नहीं पा सकते! राष्ट्रीय विखंडन और पाखंड का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। युवा पीढ़ी का पूरा भविष्य ही दांव पर लगा हुआ है, इसलिए नौजवान झांसे में नहीं आ रहे। आसार यही दिख रहे हैं कि 'सबके लिए रोजगार' का नारा सड़क से संसद तक लंबे समय तक गूंजता रहेगा।